समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Friday, 25 September 2026

महाराष्ट्र मे हंर तालुका मे बंनेगें 10 स्मार्ट गाँव : फड़णवीस सरकार की नई योजना से ग्रामीण विकास को गति

Publisher

Published on 25 Aug 2025

महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण विकास को नई दिशा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने कहा है कि **राज्य के हर तालुका मे 10 स्मार्ट गाँव विकसित किए जाएंगे।**

इस योजना का उद्देश्य केवल आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराना ही नहीं है, बल्कि ग्रामीण इलाकों को **डिजिटल, स्वच्छ, आत्मनिर्भर और आधुनिक तकनीक आधारित** बनाना है।

स्मार्ट गाँव की परिकल्पना

“स्मार्ट गाँव” का मतलब सिर्फ पक्की सड़कें या बिजली तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बहुआयामी विकास मॉडल है जिसमें शामिल हैं:

1. **डिजिटल कनेक्टिविटी** – इंटरनेट और ई-गवर्नेंस सेवाओं तक आसान पहुँच।
2. **शिक्षा और स्वास्थ्य** – ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म और टेलीमेडिसिन सुविधाएँ।
3. **सौर और हरित ऊर्जा** – सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के ज़रिए बिजली की व्यवस्था।
4. **स्मार्ट कृषि तकनीक** – ड्रोन, सेंसर और आधुनिक सिंचाई तकनीक का इस्तेमाल।
5. **कचरा प्रबंधन और स्वच्छता** – ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और साफ़-सुथरा गाँव।
6. **आर्थिक सशक्तिकरण** – छोटे उद्योग, स्वरोजगार और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम।

योजना का खाका

देवेंद्र फड़णवीस के अनुसार, इस योजना के लिए राज्य सरकार विशेष फंडिंग उपलब्ध कराएगी।

- **हर तालुका** में 10 गाँव चुने जाएंगे।
- चयन के मानदंड होंगे – जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति, सामाजिक–आर्थिक स्थिति और विकास की आवश्यकता।
- राज्य सरकार, जिला प्रशासन और ग्राम पंचायत मिलकर इस योजना को लागू करेंगे।
- PPP मॉडल (Public-Private Partnership) के ज़रिए भी कई प्रोजेक्ट्स पूरे किए जाएंगे।

क्यों ज़रूरी है स्मार्ट गाँव योजना ?

भारत की आधी से अधिक आबादी गाँवों में रहती है। महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में ग्रामीण विकास एक बड़ी चुनौती है।

- **शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी** – ग्रामीण इलाकों में अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ अब भी दूर की चीज़ हैं।
- **रोज़गार संकट** – गाँवों में पर्याप्त रोज़गार न होने से पलायन बढ़ रहा है।
- **डिजिटल गैप** – इंटरनेट और तकनीक की पहुँच अब भी सीमित है।

स्मार्ट गाँव योजना से इन समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश होगी।

संभावित लाभ

1. **रोज़गार सृजन** – गाँवों में छोटे उद्योग और स्टार्टअप बढ़ेंगे।
2. **पलायन पर रोक** – ग्रामीण युवाओं को गाँव में ही अवसर मिलेंगे।
3. **आधुनिक शिक्षा** – डिजिटल क्लासरूम और स्किल ट्रेनिंग सेंटर से बच्चों और युवाओं को नया प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा।
4. **स्वास्थ्य सुधार** – टेलीमेडिसिन और मोबाइल हेल्थ यूनिट्स से स्वास्थ्य सेवाएँ सुलभ होंगी।
5. **महिला सशक्तिकरण** – स्वयं सहायता समूहों और छोटे उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा।

चुनौतियाँ भी कम नहीं

हालाँकि यह योजना सुनने में आकर्षक है, लेकिन इसके सामने कई चुनौतियाँ हैं:

- **वित्तीय संसाधन** – हर तालुका में 10 गाँवों का स्मार्ट मॉडल विकसित करना करोड़ों रुपये का प्रोजेक्ट होगा।
- **तकनीकी अड़चने** – गाँवों में इंटरनेट और बिजली की उपलब्धता अभी भी सीमित है।
- **प्रशासनिक बाधाएँ** – योजनाओं का ज़मीनी स्तर पर सही क्रियान्वयन हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है।
- **स्थानीय सहयोग** – गाँवों के निवासियों की भागीदारी और समर्थन बेहद ज़रूरी होगा।

ग्रामीणों की उम्मीदे

गाँवों के निवासियों ने इस घोषणा का स्वागत किया है। कई लोगों का मानना है कि अगर यह योजना सही ढंग से लागू हुई, तो यह गाँवों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है।

- एक किसान ने कहा – “अगर हमें स्मार्ट कृषि उपकरण और सिंचाई तकनीक मिले, तो पैदावार दोगुनी हो सकती है।”
- एक ग्रामीण महिला ने कहा – “महिला समूहों को प्रोत्साहन मिलेगा तो हमें स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे।”

विपक्ष की प्रतिक्रिया

विपक्षी दलों ने सरकार की घोषणा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि “पिछली कई योजनाएँ सिर्फ कागजों तक सीमित रह गईं।” उनका आरोप है कि सरकार चुनाव से पहले ग्रामीणों को लुभाने के लिए बड़े वादे कर रही है।

हालाँकि, सत्ता पक्ष का कहना है कि यह योजना दीर्घकालिक और ठोस होगी।

“हर तालुका में 10 स्मार्ट गाँव” योजना महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास के लिए **एक नया रोडमैप** साबित हो सकती है। अगर यह योजना ईमानदारी से लागू होती है तो यह न केवल गाँवों की तस्वीर बदलेगी, बल्कि राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में भी बड़ी भूमिका निभाएगी।

अब नज़रें इस पर टिकी हैं कि सरकार इसे ज़मीनी स्तर पर कैसे लागू करती है और क्या यह योजना वास्तव में ग्रामीण भारत के लिए “**स्मार्ट भविष्य**” की राह खोल पाएगी।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.